

टैक्स सुधार 'रैपिड', गति पर

जब पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अधिकारियों को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि राजकोष के लिए राजस्व जमा करते समय वे रैपिड (आरएपीआईडी) का पालन करें। 'राजस्व ज्ञान संगम' के समापन पर वरिष्ठ टैक्स अधिकारी रैपिड का संदेश ले कर चले। इसका अर्थ रेवेन्यू, अकाउंटेंटबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन है। प्रधानमंत्री के संदेश का निचोड़ था कि कानून का राज उन सब पर लागू हो जो टैक्स की चोरी करते हैं। लेकिन जो लोग टैक्स का भुगतान करते हैं या टैक्स का भुगतान करने की इच्छा रखते हैं वे गर्व के साथ अपने इस राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने में सक्षम हों और उन्हें किसी प्रकार का भय न हो।

करदाताओं का भय उसी समय दूर होगा जब उन्हें सही सूचना, सही कानून, उपकरणों का ज्ञान होगा और अधिकारी ईमानदारी तथा जिम्मेदारी के साथ उनसे व्यवहार करेंगे। टैक्स संबंधी कानून हमेशा से जटिल रहे हैं और ईमानदार करदाता नियमों और उप-नियमों के जाल में उलझ जाते हैं। इसके मद्देनजर सरकार यह प्रयास करती रही है कि सभी लोगों, कारोबार और उद्योगों तथा हंसी-खुशी से टैक्स देने वालों के लिए चीजों को आसान बनाया जाए। यह कहा जा सकता है कि कई बार टैक्स संबंधी कानूनों को बदल रहे हैं कठिनाई होती है क्योंकि कानूनों की छानबीन करने वाली अदालतों में मुकदमें शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले शासनकाल के दौरान पिछले तारीख से टैक्स लगाने पर जो बहस होती रही थी उसके कारण नीति बनाने में बहुत दिक्कत हुई थी। प्रतिगामी टैक्स लगाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। बहरहाल, अदालतों में लंबित मामलों का न्यायपालिका द्वारा निस्तारण किया जाएगा।

करदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए वित्त मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है कि अपाएल का बोझ कम किया जा सके। मिसाल के तौर पर

पिछले बजट में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आंतरिक अंतरण मूल्य वर्धन के दायरे को सीमित करने की घोषणा की थी। इसे कर वंचना की रोकथाम के उपाय के तौर पर वित्त अधिनियम, 2012 में शामिल किया गया था। इसी तरह, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लेखापरीक्षण के लिए आधार को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया गया। इसे संभावित आय योजना के तौर पर स्वीकार किया जाता था। व्यक्तियों और हिन्दू संयुक्त परिवार के संबंध में खातों के रखरखाव के लिए कारोबार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया। प्रोफेशनल लोगों के लिए संभावित टैक्स सीमा 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक लागू है। खातों के रखरखाव के लिए छोटे व्यापारियों की आवश्यकताओं को यह प्रावधान स्पष्ट करते हैं।

उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए कई प्रावधानों को आयकर अधिनियम में शामिल किया गया है, ताकि शेरियों के अंतरण या हितों के मद्देनजर फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को व्यापार करने में आसानी हो।

परंतु सबसे विशाल और सबसे प्रभावशाली टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के रूप में इस वर्ष जुलाई या कम से कम सितंबर तक लागू हो जाएगा। यद्यपि समस्त राजनीतिक दलों को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने संसद में इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन का समर्थन किया और यह कानून बनाने में मदद की, लेकिन प्रधानमंत्री की दृढ़ता के कारण यह संभव हो सका है। जीएसटी को लागू करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं प्रगति का जायजा ले रहे हैं और इस बात पर नजर रखे हैं कि केंद्र, राज्य और व्यापारी प्रतिष्ठान इसे लागू करें। इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से व्यापार और उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए नई दिशा मिलेगी।

पहले निर्माण आधारित कर प्रणाली लागू थी जबकि जीएसटी के तहत गंतव्य या उपभोक्ता आधारित लेवी प्रक्रिया होगी जिसमें कई टैक्सों को शामिल किया जाएगा और भुगतान आदि की

निर्बाध प्रणाली चलेगी। परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को एक ही टैक्स देना होगा जबकि पहले उन्हें सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित टैक्स या बिक्री कर या सेवा कर या चुंगी आदि देनी पड़ती थी। विभिन्न आकलन बताते हैं कि जीएसटी से देश का सकल घरेलू उत्पाद कम से कम एक से दो प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि कई कारोबार और व्यापार जो पहले टैक्स के दायरे से बाहर थे, उन्हें अब नई कर प्रणाली को अपनाना होगा। इसमें उनका अपना हित होगा और उनकी संचालन कुशलता बढ़ेगी। कीमतों पर जीएसटी के प्रभाव के विषय में जो चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, वे निर्मूल हैं। इस निर्मूल धारणा के विपरीत मध्यम और दीर्घ काल के दौरान कीमतें कम होंगी और कारोबारी क्षेत्र का वित्त ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में राज्यों की सीमाओं पर जो विलंब होता था, वह भी समाप्त हो जाएगा और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर सामान मिलेगा।

कारोबारी और औद्योगिक क्षेत्र सीबीडीटी, सीबीईसी सहित राज्य

सरकारों के साथ जीएसटी को लागू करने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके मद्देनजर कर्मियों का प्रशिक्षण हो रहा है और कारोबारी हल्के के साथ बातचीत चल रही है। आरंभिक चरणों में व्यापारिक संस्थानों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि अगर जीएसटी आधारित प्रणाली को अपनाने में कोई गैर-इरादी तौर पर कमी रह जाए तो उसके लिए छूट दी जाए। संभवतः इस समस्या को जीएसटी परिषद देख सकती है क्योंकि इस तर्क में दम है। बहरहाल, जीएसटी को सफल बनाने और भारत के टैक्स सुधारों को आदर्श के तौर पर पेश करने में बहुत कुछ दांव पर लगा है।

जीएसटी के कार्यान्वयन पर विश्व रेटिंग एजेंसियां और बहुस्तरीय संगठन नजदीकी नजर जमाए हुए हैं। इसका आसान कार्यान्वयन व्यापार करने की आसानी संबंधी विश्व बैंक सूचकांक के संभवतः नैतिक रूप से भारत को आगे ले जाएगा। आंतरिक और विश्व स्तरों के लिए निवेश के संबंध में प्रावधान एक प्रमुख पैमाना होता है। अब भारत सही दिशा में चल पड़ा है।

85 वैश्विक टीमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विकसित करेंगी परिवर्तनकारी तकनीकी समाधान

एक्स प्राइज, जो मानवता की बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं को डिजाइन करने और उनके संचालन में वैश्विक लीडर है, ने आज 10 लाख डॉलर की अनु और नवीन जैन महिला सुरक्षा एक्सचेंज प्राइज प्रतियोगिता के लिए 18 देशों की 85 टीमों की घोषणा की। यह एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है, जो दुनियाभर की टीमों को एक ऐसा किरायाती टेक्नो लॉजी समाधान विकसित करने की चुनौती देती है, जिसका महिलाएं खतरों से त्वरित निपटने में सक्षम हो सकें। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में कार्यरत पांच विशेषज्ञों के एक सलाहकार बोर्ड की भी आज घोषणा की गई। यह बोर्ड महिला सुरक्षा एक्सचेंज प्राइज में अपनी

सलाह देगा। प्रतियोगी टीमों में एप डेवलपर्स, टेक्नो लॉजी रिसर्चर्स, शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थान और स्टाइल अप्स शामिल हैं, जो दुनियाभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं।

यह वैश्विक प्रतिस्पर्धा टीमों को टेक्नोलॉजी के उपयोग से परिवर्तनकारी समाधान के साथ समाज को सशक्त बनाने की चुनौती देता है, जो महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इस समाधान में आपातकालीन चेतावनी देने के लिए एक स्वोचाली संयुक्त एप स्ट्रिगर होना चाहिए और यह 90 सेकेंड के भीतर सामुदायिक उत्तरदाताओं तक जानकारी पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। विजेता टीमों लॉजी की लागत 40 डॉलर से अधिक नहीं होनी चाहिए। (19-10)

सुनील कुमार गर्ग पश्चिम रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

भारतीय रेल यातायात सेवा के 1985 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री सुनील कुमार गर्ग ने पश्चिम रेलवे, मुंबई के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक का कार्यभार हाल ही में ग्रहण कर लिया है।

श्री गर्ग सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा संरचनात्मक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं। पश्चिम रेलवे पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पद पर नियुक्त होने से पूर्ण श्री गर्ग दक्षिण रेलवे के मद्रुराई मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। श्री गर्ग ने विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है तथा वाणिज्य, परिचालन तथा संरक्षा विभाग में कार्य करने का इन्हें गहन अनुभव प्राप्त है। श्री गर्ग ने प्रशिक्षण



तथा अध्ययन कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2012 में शंघाई तथा पेरिस एवं वर्ष 2016 में इटली के मिलानो की यात्राएं भी की हैं।

वोल्वो कार्स ने अपने 'मेक इन इंडिया' प्लान की घोषणा की



नई दिल्ली, प्रीमियम कार निर्माता वोल्वो कार्स ने आज 2017 से भारत में वाहन निर्माण शुरू करने की घोषणा की। इससे भारत के तेजी से बढ़ते प्रीमियम कार सेगमेंट में कम्पनी का बेहतर कारोबार होगा। असेम्बली का काम दक्षिण भारत में बंगलुरु के पास होगा जहां वोल्वो के एसपीए मांड्युलर वाहन के आर्किटेक्चर पर आधारित मॉडलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहां असेम्बल होने वाले वोल्वो का पहला मॉडल XC90 प्रीमियम SUV होगा। देश में असेम्बल होने वाले अन्य मॉडलों की बाद में घोषणा की जाएगी। असेम्बली कारोबार लगाने के लिए वोल्वो कार्स ट्रक, बस, कस्टमर मर्चें

और पेट्टा इंजन के निर्माता वोल्वो ग्रुप इंडिया के साथ काम करेगी और बंगलुरु के पास उपलब्ध वोल्वो ग्रुप इंडिया के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ उसके प्रोडक्शन लाइसेंस का उपयोग करेगी। इस करार और वित्तीय विवरण की अधिक जानकारी नहीं दी जागी। "हमें इसी साल मेड इन इंडिया वोल्वो कार की बिक्री शुरू करने की बड़ी प्रसन्नता है," वोल्वो कार्स के प्रेजिडेंट और सीईओ हकान सैम्युल्सन ने कहा। "भारत में वाहन निर्माण वोल्वो कार्स के लिए एक बड़ा कदम है। हम तेजी से बढ़ते इस बाजार में बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य आने वाले वर्षों में लक्ष्मी सेगमेंट में अपना मार्केट शेयर दोगुना करने का है।" (20-4)

भारत फलस्तीन के लोगों की उनके विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है-राष्ट्रपति

राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में फलस्तीन के राष्ट्रपति महामहिम श्री महमूद अब्बास का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में एक प्रतिभोज की भी मेजबानी की। फलस्तीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने अक्टूबर 2015 में फलस्तीन की अपनी यात्रा एवं फलस्तीन की सरकार तथा वहां के लोगों के भावभीने स्वागत का स्मरण किया। राष्ट्रपति महोदय ने श्री महमूद को फतेह पाटी के चैयरमैन के रूप में उनके पुनर्निर्वाचन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री महमूद के पुनर्निर्वाचन के साथ फलस्तीन के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिक

आकांक्षा शांति और मजबूत नेता की है, जो उन्हें उनकी आकांक्षाओं की दिशा में आगे ले जाये। राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत, फलस्तीन के साथ अपने द्वीपक्षीय सम्बन्धों को काफी महत्व देता है, जिसमें हाल के वर्षों में काफी गति आई है और वृद्धि हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक विस्तारित होगा।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि फलस्तीन के ध्येय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और फलस्तीन के लोगों के साथ भारत की मित्रता देश की विदेश नीति का एक अंदरूनी हिस्सा बन चुका है।

गोडैडी ने 2017 'वर्ल्ड होस्टिंग डेज' एवं 'नेम्सकॉन' इंडिया की टाईटल स्पॉन्सरशिप की घोषणा की



छोटे, स्वतंत्र वेंचर्स के लिए समर्पित दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म गोडैडी इंक (NYSE: GDDY) ने आज आगामी सबसे बड़ी स्वतंत्र होस्टिंग एवं क्लाउड सर्विसेस कॉन्फ्रेंस WHD.india तथा दुनिया के सबसे बड़े डोमेन नेम इंडस्ट्री ईवेंट, NamesCon India के लिए अपनी टाईटल स्पॉन्सरशिप की घोषणा की। यह भारत में पहला नेम्सकॉन होगा, जिसका आयोजन मुंबई में 18-19 मई, 2017 को ग्रांड हयात में WHD.india के सातवें संस्करण के साथ होगा।

WHD.india 2017 के पहले दिन 500 से अधिक रिसेलर्स, वेब

डेवलपर्स, वेब डिजाईनर्स तथा उद्योग की बड़ी हस्तियां हिस्सा लेंगी। दूसरा दिन नेम्सकॉन को समर्पित होगा, जिसमें 200 से अधिक डोमेन इन्वेस्टर, ब्लॉगर तथा डोमेन रिसर्चर हिस्सा लेंगे। टाईटल स्पॉन्सर होने के अलावा रघु मूर्ति, गोडैडी, सॉनियर वाइड प्रेसिडेंट-होस्टिंग प्रोडक्टर डेवलपमेंट, WHD.india में "बॉलीवुड से सीखे गए 10 पाठ, जो वेब होस्टिंग का भविष्य बनाते हैं" विषय पर भाषण देंगे। इसके अलावा होस्टिंग के वर्तमान ट्रेंड्स पर चर्चा का आयोजन भी होगा। इस ईवेंट में उद्योग के अन्य लीडर्स एवं विशेषज्ञों के द्वारा प्रमुख संबोधन तथा जानकारियों के सत्र होंगे। (20-4)

डीएसपी ब्लेकरोक इक्विटी फंड ने 20 साल पूरे किये, 20 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा दिया

भारतीय बजार का सूचकांक नये रिकार्ड स्तर पर देखा जा रहा है और भारत वृद्धि के चरण में आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा इस चालू वर्ष अधिक बारिश होने की भविष्यवाणी करने के चलते अर्थतंत्र मजबूत बनेगा। तथा आगामी समय में भी अर्थतंत्र की वृद्धि की गति बनी रहेगी। डीएसपी ब्लेकरोक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड अपना डीएसपी ब्लेकरोक इक्विटी फंड के कामकाज के सफलता 20 वर्ष मना रहा है। 29 अप्रैल, 1997 को स्थापित इस फंड ने निफ्टी-500 बेन्चमार्क के 13.16 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से मुआवजा देने की तुलना में समान समयवधि में इसकी शुरूआत से वार्षिक 20.8 प्रतिशत के चक्रवृद्धि दर से मुआवजा दिया है। जिसके चलते इक्विटी मल्टी-केप केटेगरी के ऊंच स्तर 3 फंड्स में इसका समावेश किया गया है।

विशेषज्ञों के मतानुसार देश में आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उद्योग साहसिकता का माहौल सकारात्मक है और तमाम कारोबार में

मूल्य वर्धन की अच्छी संभावनाएं हैं। ऐसे में आगामी एक दशक तक इक्विटी चयन की अस्क्रायमत्त के रूप में स्थान बना रहेगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। गत 25 वर्ष के दौरान युएस बोण्ड में वृद्धि के पांच अलग-अलग अवधि निरीक्षण के दौरान भारतीय इक्विटी में से मिलता औसत तिमाही मुआवजा सतत मजबूत देखा गया है।

इक्विटी आधारित निवेश साधन दीर्घकालिन होता है जो लंबे समय में समृद्ध बनाता है इस मामले निवेशकों को समझाने की जरूरत है। संपूर्ण डेट आधारित निवेश में मुआवजे की तुलना में इक्विटी आधारित साधन में किया गया निवेश चक्रवृद्धि दर के कारण 1-2 परसेंट पोइंट ऊंचा मुआवजा भी आपको अल्पा लाभ दे जाता है। अधिकांश निवेशक बजार की ऊंचाई-गिरावट के आधार पर रोज रोज आपको मुनाफा-नुकसान की गणना करने की आदत वाले होते हैं। ऐसे निवेशक केवल अल्पकालीन कामकाज पर नजर रखते हैं और अगर कामकाज ठीक न हुआ तो देर-सबेर अपना निवेश बेचकर गलत जगह पर निवेश कर देते हैं। (11)

एक कॉमेडियन की निगाह से देखें एक भारतीय शहर!



ट्यून-इन नोट कला, संस्कृति और व्यंजनों का शहर; खुशियों की चमक से भरा एक शहर, एक शहर जहाँ 8,000 रिक्शावाले और लगभग 2,50,000 बेघर लावारिस बच्चे रहते हैं, काम करते हैं और सोते हैं। यह शहर है- कोलकाता शहर। एक अंग्रेज कॉमेडियन को कैसा लगता है यह शहर? जानने के लिए सोनी बीबीसी आर्थ अपन नए शो 'कोलकाता विद यू पर्फेन्स' के जरिये आपको ले चल रहा है होस्ट एवं कॉमेडियन सू पर्फेन्स' के साथ एक

अज्ञात सफर पर, 21 मई, 2017 को रात 10:00 बजे। इस शहर के अभी तक के अनजाने पहलुओं को दिखाने के लिए सू एक साहसिक सफर की शुरूआत कर रहे हैं। दमदार कहानियों के साथ जीवंतता का अनुभव करें जिनमें कोलकाता की जिंदादिली को दर्शाया गया है। लिहाजा, एक ऐसी स्थल के दिलचस्प परिज्ञान को देखना नहीं भूलें जो अपने गूढ़ अतीत से अभी तक बंधा हुआ है, फिर भी एक उज्वल भविष्य की ओ उम्मीद रखता है। (20-4)

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) - असम की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री , श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि आज कैबिनेट ने शत प्रतिशत परिव्यय के साथ असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी 587 एकड़ भूमि पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) असम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

श्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि आईएआरआई- असम कृषि शिक्षा के उच्चतर अध्ययन का एक स्नातकोत्तर संस्थान होगा और इसमें खेत फसलों, बागवानी फसलों, कृषि वानिकी, पशु पालन, मात्स्यिक, कुक्कुट पालन, शुकर पालन, रेशम कोट पालन, शहद उत्पादन आदि जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों समेत वे सारी हॉलमार्क पहचान होंगी जो नई दिल्ली के आईएआरआई में है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि आईएआरआई असम द्वारा पूर्वोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र के समग्र और टिकाऊ विकास के लिए उत्पादकता, गुणवत्ता

एवं लाभप्रदता बढ़ाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने, किसान अनुकूल प्रौद्योगिकियों के सृजन की दिशा में अपने मिशन में अनुसंधान, शिक्षा विस्तार कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए सभी वर्तमान केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों के समन्वय से पूर्वोत्तर भारत की कृषि चुनौतियों एवं जटिलताओं पर कार्य किया जाएगा।

श्री सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि विकास के लिए असम में आईएआरआई स्थापित किया जाएगा। छ माह पहले असम की नयी सरकार ने धेमाजी ने जमीन दी है। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है अब निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

थावरचंद गहलोत ने दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों की 15वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज यहाँ दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन समीक्षा के लिए दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों की 15वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया। दो दिन की यह बैठक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के दिव्यांगजन के लिए आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित की गयी है।

इस अवसर पर दिव्यांगजन के लिए मुख्य आयुक्त श्री कमलेश पाण्डेय, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के सचिव श्री एन.एस.कांग उपस्थित थे। दिव्यांगजनों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्त इस बैठक में भाग ले रहे हैं और अपने-अपने राज्यों में अधिनियम लागू करने के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग काफ़ी प्रगति के प्रतिनिधियों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया।

शनिवार रात 9 बजे कमान्डो 2 का वर्ल्ड टेलिविजन प्रीमियर



भ्रष्टाचार विरोधी वैश्विक नागरी समाज संस्था ट्रांसपरन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण अनुसार किए गए 16 एशिया पेसिफिक देशों में भारत में रिश्वत के मामले सबसे अधिक है। भारत में हर 10 में से 7 लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। काले धन के व्यवहारों को रोकने के लिए नवम्बर, 2016 में सरकार ने अचानक 500 और 1000 की नोट पर प्रतिबंध लगाने से राष्ट्रभर में भारी हंगामा मच गया। खास कर काला धन रखने वालों का जीवन दुष्कर बन गया। भारत सरकार काले धन के इस दूषण को रोकने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ऐसे में हिन्दी फिल्मों के लिए दुनिया का सबसे विशाल फिल्मी रंगमंच जी सिनेमा काले धन के विरुद्ध लड़ाई की ऐसी ही कहानी लेकर आ रही है। इसके तहत 20 मई रात 9 बजे से कमान्डो 2

का वर्ल्ड टेलिविजन प्रीमियर प्रसारित किया जाएगा। मार्शल आर्ट्स फाइटर और एक्शन हीरो विद्युत जामवाल के साथ अलहा शर्मा, ईशा पेसेफिक देशों में भारत में रिश्वत के मामले सबसे अधिक है। भारत में हर 10 में से 7 लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। काले धन के व्यवहारों को रोकने के लिए नवम्बर, 2016 में सरकार ने अचानक 500 और 1000 की नोट पर प्रतिबंध लगाने से राष्ट्रभर में भारी हंगामा मच गया। खास कर काला धन रखने वालों का जीवन दुष्कर बन गया। भारत सरकार काले धन के इस दूषण को रोकने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ऐसे में हिन्दी फिल्मों के लिए दुनिया का सबसे विशाल फिल्मी रंगमंच जी सिनेमा काले धन के विरुद्ध लड़ाई की ऐसी ही कहानी लेकर आ रही है। इसके तहत 20 मई रात 9 बजे से कमान्डो 2 का दूसरा हप्ता है। कमान्डो 2 में दिलधड़क स्टंट्स (विद्युत जामवाल ने किसी भी स्टंट डबलस या अश्वसज्जा का उपयोग नहीं किया) दिखाई देगी। कमान्डो करणवीर सिंग डोगरा (विद्युत जामवाल) वन मेन आर्मी के तौर पर भारत में काला धन लाने वाले आंतरराष्ट्रीय मिशन पर निकल पडी है। (19-8)

संपादक-चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक-मयूर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल-201, 202, 208 नंदन कॉम्प्लेक्स, मीठाखली, अहमदाबाद-6. मालिक-कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी-4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन-26568477, 26409779. E: alpaviram1@yahoo.com

सूचना
कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई-मेल पर ही भेजें :
alpaviram@gmail.com